



भारत का राजापत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रापिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 1991/फाल्गुन 2, 1912

No. 71] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 1991/PHALGUNA 2, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन ले सक्य थे
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

संकलन

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1991

सा.का.नि. 85(म).—(1) सरकार ने पर्यावरण की दूषित से अनुकूल पश्चात्यों की लेबल लगाने की एक स्कोम चलाने का निर्णय लिया है। यह स्कीम राष्ट्रीय भर पर लागू होगी और इसमें ऐसे घरेलू तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों के प्रत्यायन और लेबल लगाने की व्यवस्था होगी, जो उस उत्पाद के लिए निर्धारित भारतीय भानकों की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी कुछ सापेक्षणिक भी पूरा करते हों। इस लेबल को “ई-टोमार्ट” कहा जायेगा। आर इसको डिजाइन बाद में अधिसूचित की जायेगी।

कोई भी उत्पाद जिसका निर्माण, प्रयोग अथवा निपटान ऐसे तरीके से किया जाता है, जिससे उससे अन्यथा होने वाला नुकसान काफी हृदय का भय हो जाता है तो उसको पर्यावरण की दूषित से अनुकूल उत्पाद कहा जा सकता है।

(2) स्कोम के उद्देश्य :

इस स्कोम के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है:—

(1) उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विनियोजित और आवाहकों को प्रोत्साहन देना।

(2) कम्पनियों के उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उनके द्वारा वास्तविक पहल करने पर उन्हें पुरस्कार देना।

(3) उत्पोक्ताओं के खरीद संबंधी नियमों में पर्यावरणीय तथ्यों को ध्यान में रखने की जानकारी प्रदान करके उन्हें उनके वैज्ञानिक जीवन में पर्यावरण के प्रभु सेवा बनाने में मदद करना।

(4) नागरिकों को ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होनिकारक हो।

(5) अलंकारी पर्यावरण के स्तर में सुधार करना और संसाक्षणों के सतक प्रबंध को प्रोत्साहित करना।

(3) प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचा

तीन घरणों के अन्त में “इकोमार्क” प्रदान किया जायेगा :—

- (1) स्कीम के तहत आपे वाले उत्पाद श्रेणियों के निर्वाचन के लिए तथा स्कीम कार्यप्रणाली के संबंधन, कार्यालय, भावी विकास और सुधार के लिए नीतियों के निर्धारण के लिए एवं विरण और वन मंत्रालय में स्थापित एक संचालन समिति ।
- (2) चूंकि जान आणि विशिष्ट उत्पाद और अपनाये जाने वाले अलग-अलग मापदण्ड, तथा एक से अधिक भाष्यांक होने पर उनके बीच व्यापारिय परस्परिक प्राप्तिकाता के अभिनिवृत्ति के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में हवायित एक तकनीकी समिति ।
- (3) उत्पादों के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए तथा एक शूलक का भुगतान करने पर नेटवर्क के प्रयोग की प्रनुभवित देने के लिए नीतियों के माध्यम संविधा वैधान वरने के लिए भारतीय मानक बूर्ड ।

3.1.1 संचालन समिति

स्कीम के तहत लायी जाने वाली उत्पाद श्रेणियों के बारे में निर्णय लेने वाला इस स्कीम के संबंधन, भावी विकास और सुधार के लिए नीतियों के निर्धारण के लिए केन्द्रीय सुरक्षार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक संचालन समिति स्थापित की जायेगी । उत्पाद श्रेणियों के विवरण पर अधिकृति की जायेगी ।

संचालन समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :—

- (क) “इकोमार्क” के लिए शब्दावली का निर्माण ।
- (ख) स्कीम के संबंधन और स्वीकृति के लिए जन-जागरूकता पैदा करने संबंधी गतिविधियाँ ।
- (ग) स्कीम के तहत लायी जाने वाली उत्पाद श्रेणियों का निर्धारण ।
- (घ) उदांग की इस स्कीम में संकेत भागोंवारी सुनिश्चित करने के लिए तरीकों का समन्वय करना ।
- (ङ) अन्य मंत्रालयों, सरकारी विभागों, उत्पाद, एसोसिएशनों तथा अन्य और सरकारी संगठनों और उपभोक्ता संगठनों की भावीतारी प्राप्त करना ।
- (च) स्कीम के भावी विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करना ।
- (छ) किसी वस्तु या प्रक्रिया के मानकीकरण प्रयोग किसी वस्तु या प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार के भाव में लगी भारतीय अपेक्षा बाह्य संस्थाओं की अभिनिवृत्ति करना; तथा उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए सहायता की सिफारिश करना ।
- (ज) उपभोक्ता संगठनों द्वारा उत्पादों को सुलनात्मक जांच के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और उनके परिवर्त्यों का आम जनता में प्रचार करना ।

(1) उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं के हित में “इकोमार्क” उत्पादों के निर्धारण के लिए किये जाने वाले प्रनुभवित नीति के लिए उपभोक्ता जागरूकता के लिए विभिन्न विधियों को अपनाएं जा रहे पर्यावरणीय मापदंडों की समीक्षा ।

समिति की संस्करणा निम्नलिखित होगी :—

- (1) सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग अध्यक्ष
- सचिव, नागरिक भाष्यांक (या उनके प्रतिनिधि) नवस्य
- सचिव, उदांग मंत्रालय (या उनके प्रतिनिधि) नवस्य

- (4) सचिव, रसायन और पेट्रो-केमिकल मंत्रालय (या उनके प्रतिनिधि) सवस्य

- (5) सचिव, शूष्य मंत्रालय (या उनके प्रतिनिधि) सवस्य

- (6) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (या उनके प्रतिनिधि) नवस्य

- (7) महानिवेशक, सकर्ता की विकास (या उनके प्रतिनिधि) सवस्य

- (8) महानिवेशक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिवर्त (या उनके प्रतिनिधि) सदस्य

- (9) महानिवेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ (या उनके प्रतिनिधि) सवस्य

- (10) विकास आयुक्त, संघ उदांग (या उनके प्रतिनिधि) सवस्य

- (11) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नवस्य

- (12) उदांग, उपभोक्ता दलों तथा अन्य और मरकारों संगठनों के हितों को देखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले, और सरकारी सवस्य जिनकी संभावा पांच से अधिक न हो, इनमें से कम से कम दो सवस्य उपभोक्ता दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

- (13) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में “इकोमार्क” प्रभारी अधिकारी ।

सवस्य सचिव

विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष अपेक्षित विशेषज्ञ के माध्यमे में, समिति विशेषज्ञों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकती है ।

समिति की अवधि तीन वर्ष या आगामी पुनर्गठन तक के लिए होगी ।

3.1.2 तकनीकी समिति

विशिष्ट उत्पादों की पहचान और मापदंड निर्धारित करने हेतु “इकोमार्क” प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षार द्वारा एक तकनीकी समिति का गठन किया जानायी केन्द्रीय मंत्री, प्रूबग नियंत्रण बोर्ड, नई विद्यों के विवेद कार्यक्रमों की जांच करेगी ।

तकनीकी समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

- (1) पर्यावरण की दृष्टि से प्रनुकूल जैसे वर्तीकरण के लिए विशिष्ट उत्पादों की विशेषज्ञ करना ।

- (2) अन्य वेशों में भौजूदा जानकारी और अपनाएं जा रहे पर्यावरणीय मापदंडों की समीक्षा ।

- (3) विभिन्न “उत्पादों की पर्यावरण की दृष्टि से प्रनुकूल नामोंविष्ट करने के लिए उपयुक्त मापदंड और पैरामीटरों की सिफारिश करना, इनमें प्रत्येक उत्पाद के लिए वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मापदंड भी सामिल है, जिसे इस प्रयोगजन तथा अहा सम्बद्ध हो, उनकी परस्पर प्राप्तिकाता के सिए विविष्ट किया गया है ।

- (4) मापदंड के निर्धारण के लिए उत्पादव्यविधि प्रयोगिकीयों की समीक्षा ।

- (5) उत्पादों के मूल्यांकन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को विभिन्न प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञों की सिफारिश करना ।

- (6) समय समय पर उत्पादों के पर्यावरणीय प्रसार और मापदंडों का सुस्थीकरण ।

(७) भारतीय मानक ध्यूरों द्वारा समय समय पर स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, जिनमें इन्हें द्वारा किए गए नमूना निरीक्षण भी आते हैं।

(८) उपभोक्ता संगठनों द्वारा उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण के लिए परीक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने सहित यदि अधिकारी हों तो प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए उपसमितिया गठित करना।

(९) विशिष्ट उत्पादों के बारे में तकनीकी समिति को सलाह देने के लिए यह विशेषज्ञों का पैनल बना सकती है।

समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

(१) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रबूषण नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष
(२) महानिदेशक, भारतीय मानक ध्यूरों, नई विली	सदस्य
(३) निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग नमूनेंधान संस्थान, नागपुर।	सदस्य
(४) निदेशक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे	सदस्य
(५) महानिदेशक, नेशनल टेस्ट हाउस, फलकता	सदस्य
(६) निदेशक, भौतिकीय विज्ञ-विज्ञान नमूनेंधान, संस्थान, लखनऊ।	सदस्य
(७) निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद।	सदस्य
(८) उद्योग तथा उपभोक्ता द्वारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गैर-सरकारी सदस्य, जिनकी संख्या ५ से अधिक न हो, इनमें से तीन केन्द्र सरकार द्वारा नामंदग दस्तावेज सदस्य उपभोक्ता द्वारों का प्रतिनिधित्व करें।	सदस्य
(९) प्रभारी अधिकारी (इको मार्क स्कीम), केन्द्रीय प्रबूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य-सचिव

समिति विभिन्न उत्पादों के बारे में विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर सहयोगित कर सकती है।

समिति का कार्यकाल तीन मास या इसके पुनर्गठन होने तक है।

३. १. ३ प्रशासन :

भारतीय मानक ध्यूरों स्कीम का कार्यान्वयन करेगा। भारतीय मानक ध्यूरों के कार्यान्वयन की नियन्त्रित होंगे :—

(१) इको-मार्क के लिए उत्पाद का मूल्यांकन, इको मार्क देने के लिए उत्पाद का प्रमाण।

(२) इको-मार्क के प्रयोग के लिए लाइसेंस को नियंत्रित, रद्द करने के बारे में समीक्षा करना।

(३) निरीक्षण करना और किसी ज़रूरी सामग्री अथवा 'पदार्थों के विश्लेषण के लिए नमूने लेना, ताकि यह पता चल सके कि क्या कोई वस्तु या उत्पाद, जिसके संबंध में इकोमार्क का प्रयोग किया गया है, अनुग्रह के अनुरूप है अथवा इकोमार्क का किसी वस्तु या प्रक्रम के संबंध में लाइसेंस सहित या लाइसेंस के बिना प्रयोग किया गया है।

(४) प्रमाणन और लाइसेंस देना :

४. १ इस स्कीम के अन्तर्गत, नियन्त्रिकार्ताओं द्वारा उन उत्पादों के अन्तर्काश तथा प्रमाणन के लिए जो मुद्रित पर्यावरणीय मानवंड के अनुसार उत्पादक प्रत्युपलग्न के लिए अधिकृत अधिकारी के अन्तर्गत आते हों, नियन्त्रित कार्य में आवेदन करें। शुल्क सहित लाइसेंस से संबंधित शर्तें

भारतीय मानक ध्यूरों अधिकृतियम तथा उसके तहत बने विनियमों के अनुसार होंगी।

४. २ परीक्षण और प्रमाणन भारतीय मानक ध्यूरों द्वारा किया जायेगा। भारतीय मानक मार्क वाली उत्पाद श्रेणियों के लिए भारतीय मानक ध्यूरों प्रमाणन के कार्य को सामान्यतया तीन माह के भीतर पूरा करेगा। इकोमार्क के लिए पात्र प्रमाणित वस्तुओं को नियन्त्रित अवधि के लिए इको मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जायेगा।

४. ३ नियन्त्रित अवधि के बाद उत्पाद का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तथा मार्क के लिए पुनः लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

५. इकोमार्क के लिए मापदंड :

प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय मापदंड अधिकृत किया जायेगा तथा बाद में भारतीय मानक ध्यूरों द्वारा भारतीय मानकों में बदला जायेगा।

मापदंड अधारक पर्यावरणीय स्तरों तथा पहलुओं के लिए बनाए जाएंगे जो विशेष रूप से उत्पाद स्तर के लिए होंगे। उत्पादों की जांच नियन्त्रित मुद्रित पर्यावरणीय प्रमाणों के संबंध में की जाएगी :—

(क) उपयोग तथा निपटान प्रक्रिया में अन्य उत्पादों की तुलना में कम प्रबूषण फैलाने वाले उत्पाद।

(ख) जिमका पुनः प्रयोग किया जाता हो, जो पुनः प्रयोग करने योग्य होंगे और जो पुनः प्रयोग किए गए उत्पादों अथवा जैव अवकरणीय उत्पादों से बने हों, जबकि अन्य तुलनीय उत्पाद ऐसे नहीं होंगे।

(ग) जो अन्य तुलनीय उत्पादों की तुलना में गैर नवीकरणीय संसाधनों सहित गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा प्राकृतिक संसाधनों की बदल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हों।

(ज) उत्पाद के प्रयोग के संबंध में 'अधिकतम पर्यावरणीय प्रमाण' वाले प्रतिकूल प्रायमिक मापदंड में कमी करने में योगदान देना चाहिए और यह मापदंड प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए विशेष रूप से नियन्त्रित हो।

उत्पाद के लिए प्रायमिक मापदंड नियन्त्रित करने में निम्नलिखित वारों को द्यान में रखा जाना चाहिए :—

(क) कच्ची सामग्री के स्रोतों सहित उत्पादन प्रक्रिया;

(ख) प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति;

(ग) पर्यावरण पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव;

(घ) उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण;

(ज) उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट का प्रभाव तथा सीमा;

(ज) उत्पाद और उसके पात्र का निपटान;

(ज) "प्रपश्चिष्ट" तथा पुनः प्रयोग वाली सामग्री का उपयोग;

(ज) पुनः प्रयोग की प्रक्रिया अथवा पैकेजिंग के लिए उपयुक्ता;

(ज) जैव-अवकरणीयता।

मापदंड की समय समय पर पुनरीक्षा की जाएगी। जनता की 'टिप्पणियों के लिए ६० दिन के लिए मापदंड के मसौदे की प्रति प्रकाशित की जायेगी।

६. अवधि की अवधि :

लेबल कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और यांत्रिक रूप से आगे भी बढ़ता रहेगा। भारतीय मानक ध्यूरों को, भारतीय सूचना मिलने पर किसी भी समय लाइसेंस वापस लेने का अधिकार है। तकनीकी समिति के परामर्श से प्रीधारणीकी के विकास अथवा किसी

प्रथम तकरीबन कारणों से मापदंड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की स्थिति में भी अवाई वापस लिया जा सकता है। एवाई की समयावधि की समय समय पर पुनरीक्षा की जाएगी।

7. लोगों :

“इकोमार्क” के लिए “लोगों” के रूप सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

8. उपभोक्ता जागरूकता :

परिवरण और यन्म भवालय देश में उपभोक्ता दलों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ वेश्यावासी जागरूकता अभियान चलाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। उस्पावों की तुलनात्मक जांच तथा सूचना के प्रसार के लिए उपभोक्ता संगठनों को सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रावेश

प्रावेश दिया जाता है कि इस संकल्पे को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रति सभी संवैधिकों को भेजी जाए।

[23/1/91-पी एस]

15 फरवरी, 1991

मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th February, 1991

G.S.R. 85(E).—(1) The Government have decided to institute a Scheme on Labelling of Environment Friendly Products. The scheme will operate on a national basis and provide accreditation and labelling for household and other consumer products which meet certain environmental criteria along with quality requirements of the Indian Standards for that product. The Label shall be known as the “ECOMARK” and will be of the design to be notified.

Any product which is made, used or disposed of in a way that significantly reduces the harm it would otherwise cause the environment could be considered as Environment Friendly Product.

(2) Objectives of the Scheme :

The specific objectives of the scheme are as follows :—

- (i) To provide an incentive for manufacturers and importers to reduce adverse environmental impact of products.
- (ii) To reward genuine initiatives by companies to reduce adverse environmental impact of their products.
- (iii) To assist consumers to become environmentally responsible in their daily lives by providing information to take account of environmental factors in their purchase decisions.
- (iv) To encourage citizens to purchase products which have less harmful environmental impacts.

(v) Ultimately to improve the quality of the environment and to encourage the sustainable management of resources.

(3) Administrative and Organisational Structure—

There will be three stages leading to the award of the “ECOMARK” :—

1. A steering committee, set up in the Ministry of Environment and Forests, to determine the product categories for coverage under the scheme and also formulate strategies for promotion, implementation, future development and improvements in the working of the scheme.

2. A technical committee, set up in the Central Pollution Control Board, to identify the specific product to be selected and the individual criteria to be adopted, including, wherever possible, inter-se priority between the criteria if there be more than one.

3. The Bureau of Indian Standards to assess and certify the products and draw up a contract with the manufacturers, allowing the use of the label, on payment of a fee.

3.1.1 Steering Committee :

A Steering Committee shall be set up in the Ministry of Environment and Forests by the Central Government to decide the product categories to be taken up under the scheme, and to formulate the strategies for promotion, future development and improvement of this scheme. The product categories will be notified from time to time.

The functions of the Steering Committee shall be as follows :—

- (a) Selection of the logo for the “ECOMARK”.
- (b) Activities related to creation of mass awareness for promotion and acceptance of the scheme.
- (c) Determining the product category to be taken up under the scheme.
- (d) Co-ordinating ways of ensuring that industry is actively involved in the scheme.
- (e) Securing the involvement of other Ministries, Government Departments, Industry Associations and other Non-Governmental Organisations and Consumer organisations.
- (f) Formulation of strategies for future development of the scheme.
- (g) Identifying institutions in India or outside which are engaged in the standardization of any article or process or improvement of quality of any article or process and recommending assistance to build consumer awareness.
- (h) Promoting programmes of Comparative Testing of products by Consumer Organisations and dissemination their results to the general public.

(i) Supporting any research for the formulation of ECOMARK products in the interests of Consumer groups.

The composition of the Committee shall be as follows :—

- (i) Secretary, Deptt. of Environment & Forests. Chairman
- (ii) Secretary, Deptt. of Civil Supplies, (or his representative). Member
- (iii) Secretary, Ministry of Industry, (or his representative). Member
- (iv) Secretary, Ministry of Chemicals & Petrochemicals (or his representative). Member
- (v) Secretary, Ministry of Agriculture (or his representative). Member
- (vi) Secretary, Ministry of Information & Broadcasting (or his representative). Member
- (vii) Director General of Technical Development (or his representative). Member
- (viii) Director General, Council of Scientific & Industrial Research, (or his representative). Member
- (ix) Director General, Health Services (or his representative). Member
- (x) Development Commissioner, Small Scale Industries (or his representative). Member
- (xi) Chairman, Central Pollution Control Board Member
- (xii) Not more than five non officials, to be nominated by the Central Government; to represent the interests of industry, consumer groups or other non governmental organisations; of which at least two will represent Consumer groups.
- (xiii) Officer in charge, "ECOMARK" in the Ministry of Environment & Forests. Member-Secy.

In case of special requirement of expertise in specific fields, the committee may invite experts as special invitees.

The terms of the Committee shall be for three years or until reconstituted.

3.1.2 Technical Committee

A Technical Committee shall be constituted by the Central Government to identify the individual products and determine the criteria for awarding the ECOMARK. The Committee shall function in the Central Pollution Control Board, New Delhi.

The following shall be the functions for the Technical Committee :—

- (i) Identification of specific products for classifying as environment friendly.
- (ii) Reviewing the existing state of knowledge and the environmental criteria being followed in other countries.

- (iii) Recommend the most appropriate criteria and parameters to designate various products as environment friendly, including the most important criteria or individual products that have been specified for the purpose and their inter-se priority, whenever possible.
- (iv) Review the various technologies available for determining the criteria.
- (v) Recommend various laboratories and analysts for product assessment to the Ministry of Environment and Forests,
- (vi) Evaluation of the environmental impact of the products and criteria from time to time.
- (vii) To review from time to time, the implementation of the schemes by the Bureau of Indian Standards (BIS), including the sample inspections done by it.
- (viii) Set up sub-committees for each product category if so required, including formulation of test programmes for comparative testing of products by consumer organisations.
- (ix) The technical committee may set up expert panels to advise it for specific products.

The composition of the Committee shall be :—

- (i) Chairman, Central Pollution Control Board. Chairman
- (ii) Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi. Member
- (iii) Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur. Member
- (iv) Director, National Chemical Laboratory, Pune. Member
- (v) Director General, National Test House Calcutta. Member
- (vi) Director, Industrial Toxicology Research Institute, Lucknow. Member
- (vii) Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad. Member
- (viii) Note more than five non-officials to represent the interest of industry & consumer groups, of which atleast three will represent the Consumer groups be nominated by the Central Government.
- (ix) Officer in charge, (Eco-Mark scheme) Central Pollution Control Board. Member-Secy.

The Committee may co-opt experts on different products, as special invitees.

The terms of the Committee shall be for three years or until reconstituted.

3.1.3 Administration

The Bureau of Indian Standards (BIS) shall implement the scheme.

Following shall be the functions of the BIS:—

- (1) Assess the product for Ecomark, certify the product for award of the Ecomark;

(2) Review, suspend or cancel a licence, for the use of the Ecomark;

(3) Mark inspections, and take such samples for analysis of any material or substances as may be necessary to see whether any article or product in relation to which the Ecomark has been used, conforms to the contract or whether the Ecomark is improperly used in relation to any article or process with or without a licence;

(4) Certification and Licensing :

4.1 Under the scheme the manufacturers shall apply for testing and certification of products which fall under the notified categories in terms of their compliance with published environmental criteria in the prescribed form. The terms and conditions governing operations of the licences including fees shall be as per the Bureau of Indian Standards Act and the regulations framed there under.

4.2 Testing and certification shall be carried out by the Bureau of Indian Standards. For product categories which have the Indian Standards mark, the Bureau of Indian Standards will ordinarily complete the task of certification within a period of three months. Products certified as eligible for the ECOMARK shall be licensed to carry the ECOMARK for a prescribed time period.

4.3 The product shall be reassessed after the prescribed period and the licence fee shall have to be paid again for the mark.

5. The Criteria for Ecomark :

Environmental criteria for each product category will be notified by the Central Government and later on shall be translated into Indian Standards by the Bureau of Indian Standards. The criteria shall be for broad environmental levels and aspects, but will be specific at the product level. Products will be examined in terms of the following main environmental impacts :—

- (a) That they have substantially less potential for pollution than other comparable products in production, usage and disposal.
- (b) That they are recyclable, recyclable, made from recycled products or biodegradable, where comparable products are not.
- (c) That they make significant contribution to saving non-renewable resources, including non-renewable energy sources and natural resources, compared with comparable products.
- (d) That the product must contribute to a reduction of the adverse primary criteria which has the highest environmental impact associated with the use of the product, and which

will be specifically set for each of the product categories.

In determining the primary criteria for a product the following shall be taken into account :—

- (a) Production process including source of raw materials;
- (b) Case of Natural Resources;
- (c) Likely impact on the environment;
- (d) Energy conservation in the production of the product;
- (e) Effect & extent of waste arising from the production process;
- (f) Disposal of the product and its container;
- (g) Utilization of "Waste" and recycled materials;
- (h) Suitability for recycling or packaging
- (i) Biodegradability;

The criteria shall be reviewed from time to time. The draft criteria shall be released for public comments for a period of sixty days.

6. Period of Award :

The label shall be awarded for a ~~minimum~~ period of one year and shall roll forward annually. The Bureau of Indian Standards have the powers to withdraw the licence at any time if they find any misleading information. The award may also be withdrawn in case of any change in criteria due to the advancement of technology or any other valid reasons, in consultation with the technical committee. The time period of the award may be reviewed from time to time.

7. The Logo :

The Logo for the "ECOMARK" shall be as notified by the Central Government.

8. Consumer Awareness :

The Ministry of Environment & Forests shall take appropriate measures to launch a country wide mass awareness campaign, including encouraging consumer groups. Assistance will be given to consumer organisations for comparative testing of products and dissemination of information to the public.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

[No. 23/1/91-PL]

MUKUL SANWAL, Jt. Secy.
15th February, 1991